

सरकारी एवं गैर-सरकारी शिक्षण संस्थानों का वार्षिक माध्यमिक परीक्षाफल का तुलनात्मक अध्ययन: झारखण्ड राज्य अंतर्गत धनबाद जिला के विशेष संदर्भ में

¹ तरुण कुमार महतो

¹ शोध छात्र, शिक्षा विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना, बिहार, भारत।

Received: 13 June 2018, Accepted: 15 July 2018 ; Published on line: 15 Sep 2018

Abstract

झारखण्ड राज्य के झारखण्ड अधिविद् परिषद, राँची द्वारा जारी मैट्रिक का वार्षिक परीक्षाफल में टॉप के विद्यार्थी सरकारी विद्यालयों यथा नेतरहाट आवासीय विद्यालय, इंदिरा गाँधी विद्यालय आदि के विद्यार्थी टॉप पाँच में रहते हैं, पर धनबाद जिला के विगत कई सालों के परीक्षाफल में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित स्थापना अनुमति प्राप्त शिक्षण संस्थाओं का दबदबा देखा जा रहा है, इनमें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित विद्यालय हैं, जहाँ से पढ़ने वाले विद्यार्थी जिले के टॉप पाँच छात्रों में शुमार होते आ रहे हैं। टॉप पाँच विद्यार्थियों में 60 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थी इन स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालयों से हैं जो इन विद्यालयों के महत्व को बर्बाद करता है, साथ ही इस परीक्षा के नतीजों के अनुसार इन विद्यालयों में दी जा रही शिक्षा के गुणवत्ता को भी समझा जा सकता है।

विशिष्ट शब्द— गैर-सरकारी संगठन, स्थापना अनुमति प्राप्त, परीक्षाफल, ग्रामीण क्षेत्र

परिचय:

समय बदल रहा है और समय के साथ भारत में शिक्षा के विकास में भी लगातार बदलाव आता रहा है। माध्यमिक शिक्षा अंग्रेजों के आने के साथ अस्तित्व में आया। उसके पहले वैदिक कालिन और मध्यकालिन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा के केवल दो स्तर थे— प्राथमिक और उच्च शिक्षा। समय के साथ इन दोनों के बीच में एक कड़ी के रूप में माध्यमिक शिक्षा के अवधारणा ने जन्म लिया। माध्यमिक शिक्षा का समय 12 से 18 वर्ष तक माना गया है जिसमें कक्षा 9 से लेकर 12 तक की कक्षाएँ संचालित होती हैं। बच्चों के उम्र को देखने पर यह किशोरावस्था का काल माना गया है जिसे आँधी और तुफान का काल माना जाता है। इस उम्र के बच्चों में मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक आदि कई दिशा में तेजी से बदलाव आता है। इस उम्र के बच्चों में बनने और बिगड़ने दोनों की संभावना बहुत प्रबल होता है। बच्चों में किसी काम के प्रति रुचि-अरुचि इस काल में अधिक तेजी से परिलक्षित होती है। इस समय बच्चों का सही मार्गदर्शन मिलने से वे अच्छे नतीजे प्राप्त करते हैं जबकि बच्चों को सही तरीके से मार्गदर्शन नहीं मिलने पर बच्चों में बिखराव की संभावना बढ़ जाती है।

पढ़ाई के साथ भी यही बात लागू होती है। वार्षिक परीक्षाफल ही बच्चों को महाविद्यालय की शिक्षा के तरफ ले जाने में सहायक है। शिक्षक की भूमिका इस स्थिति में बहुत ही निर्णायक है। ये शिक्षक ही बच्चों के बेस्ट लेने में सहायक होता है। माध्यमिक स्तर की परीक्षा को पास करना एक बड़ी चुनौति होता है। 1854 में वुड डिस्पैच के सिफारिशों में माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए सहायता अनुदान प्रणाली का विकास करना भी एक महत्वपूर्ण सुझाव था। इसी के कारण कई निजी स्तर के प्रयास से नये माध्यमिक विद्यालय खोले गये। हंटर कमीशन, 1882-83 ने तो यहाँ तक सिफारिश कर दी थी कि जिला में केवल एक सरकारी माध्यमिक विद्यालय खोली जानी चाहिए। बाकि अनुदान सहायता देकर हर जगह निजी प्रयास से नये विद्यालय खोलने की बात कही गई। इस आयोग ने ये भी कहा था कि सरकार को केवल उन स्थानों में नये विद्यालय खोलनी चाहिए जहाँ के लोग विद्यालय खोलने में

सक्षम नहीं है। आज यही कंसेप्ट के कारण सरकारी के साथ-साथ निजी विद्यालय भी हैं जो कम शुल्क लेकर बच्चों को अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करते हैं।

शोध का महत्व:

यह सच है कि आज सरकार सरकारी विद्यालयों के साथ-साथ वैसे निजी विद्यालयों को भी स्थापना अनुमति प्रदान करती है जो सरकार द्वारा तय मापदण्ड को पूरा करती है। आज के समय में पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशीप) मॉडल को ही तरक्की के नये आयाम के तौर पर देखा जाता है। सरकारी विद्यालयों में सरकार हर क्षेत्र में सारे खर्चों का भार खुद वहन करती है, जबकि निजी विद्यालयों के प्रबंधन में विद्यालय के मैनेजमेंट कमिटी का निर्णय ही अंतिम समझा जाता है। ऐसे विद्यालयों का वित्तीय भार पूरी तरह से विद्यार्थियों से लिया गया शिक्षण शुल्क पर होता है। स्थायी स्थापना अनुमति प्राप्त सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के तुलना में निजी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का मानदेय बहुत कम होता है, इस स्थिति में क्या वे बच्चों को मन लगाकर पढ़ाते हैं कि जिससे बच्चे परीक्षा में अच्छा कर पाये, यह जानने का विषय होता है।

माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई किस स्तर तक होता है, इसका मुल्यांकन वार्षिक परीक्षाफल से ज्ञात किया जाता है। जिस विद्यालय का परीक्षाफल अच्छा होता है, स्वभाविक रूप से लोगों का ध्यान उसके तरफ अनायास चला जाता है। खासकर वैसे विद्यालय तो हमेशा सुर्खियों में आ जाता है, जहाँ के बच्चे जिला में टॉप के दस स्थानों में आते हैं। और पहले शीर्ष पाँच स्थानों में रहने वाले बच्चे जिस विद्यालय में आते हैं उसे लोग अधिक अच्छे विद्यालयों में शुमार करते हैं। ये विद्यालय चाहे निजी हो या सरकारी, उसका परीक्षाफल ही उसकी पहचान कराती है। इस बात को ध्यान में रखकर इस अध्ययन में यह तलाश किया गया है कि एन.जी.ओ. संचालित स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालय, अल्पसंख्यक और सरकारी विद्यालयों का विगत छह वर्षों का परीक्षाफल किस प्रकार हुआ है।

उद्देश्य: झारखण्ड राज्य के धनबाद जिला के सरकारी एवं गैर-सरकारी शिक्षण संस्थानों का वार्षिक माध्यमिक परीक्षाफल का तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध विधि:— इस शोध को पूरा करने के परिमाणात्मक विधि का उपयोग किया गया है। विगत कई वर्षों के वार्षिक माध्यमिक परीक्षाफल का अध्ययन समाचार पत्रों के माध्यम से किया गया, इसके आधार पर सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों के परीक्षाफल में तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

आँकड़ों का संकलन:—

शोध को पूरा करने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालयों के परीक्षाफल को देखा गया है। धनबाद जिला में माध्यमिक शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न शिक्षण संस्थाएँ हैं जिनमें राजकीय विद्यालय तीन हैं, राजकीयकृत उच्च विद्यालयों की संख्या 48 है, अपग्रेडेड राष्ट्रीय उच्च विद्यालय 56 है, कुल प्रोजेक्ट विद्यालय 05 है, अल्पसंख्यक विद्यालयों की संख्या 09 है, मदरसा विद्यालय 04 है, अनुदान प्राप्त संस्कृत विद्यालय 01 है, प्रॉप्रेटरी विद्यालय 02 है, कुल स्थापना अनुमति प्राप्त 40 विद्यालय हैं हाल में इसकी संख्या में बढ़ोत्तरी हुआ है तो कुछ संस्थाओं की मान्यता खत्म भी हुई है, बुनियादी विद्यालय 04 है, कस्तुरबा विद्यालय 06 है, केंद्रीय विद्यालय 05 है, नवोदय विद्यालय 01 है, कल्याण उच्च विद्यालय 01 है, सी.बी.एस.सी. विद्यालय 41 है और आई.सी.एस.ई. विद्यालयों की संख्या है 09 है। मैट्रिक का परीक्षाफल प्रत्येक वर्ष झारखण्ड अधिविद् परिषद, राँची द्वारा जारी किया जाता है जिसमें धनबाद जिला का प्रथम पाँच स्थानों में रहे विद्यार्थियों का पिछले छह साल के परिणाम के आँकड़े निम्नांकित सारणी— 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में दिया गया है।

सारणी-1: धनबाद जिला के वर्ष 2014 के टॉप-5 स्कूलों का परिणाम

क्रम सं०	विद्यार्थी का नाम	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	प्राप्तांक
1.	गौरव कुमार शांडिल्य	प्रोजेक्ट आरएमएस हाई स्कूल, महुदा	स्थापना अनुमति	454
2.	कौशल कुमार	एसबी हाई स्कूल, भागा	सरकारी	451
3.	प्रदीप कुमार-	मंदाकिनी हाई स्कूल, बड़ा जमुआ	स्थापना अनुमति	449
4.	राणा प्रताप सिंह	प्रोजेक्ट आरएमएस हाई स्कूल, महुदा	स्थापना अनुमति	448
5.	राजकिशोर महतो	प्रोजेक्ट आरएमएस हाई स्कूल, महुदा	स्थापना अनुमति	447

सारणी-2: धनबाद जिला के वर्ष 2015 के टॉप-5 स्कूलों का परिणाम

क्रम सं०	विद्यार्थी का नाम	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	प्राप्तांक
1.	मनीष गोप	राय एकेडमी गोविन्दपुर	स्थापना अनुमति	460
2.	सोनू कुमार	प्रोजेक्ट वनस्थली हाई स्कूल तिलैया, राँगाटाँड़	स्थापना अनुमति	451
3.	दिव्या महतो	एसएसएनएमएस हाई स्कूल, आजाद सिजुआ	स्थापना अनुमति	451
4.	निरंजन कुमार सिंह	राय एकेडमी, गोविंदपुर	स्थापना अनुमति	450
5.	मानक कुमार सिंह	राय एकेडमी, गोविन्दपुर	स्थापना अनुमति	450

सारणी-3: धनबाद जिला के वर्ष 2016 के टॉप-5 स्कूलों का परिणाम

क्रम सं०	विद्यार्थी का नाम	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	प्राप्तांक
1.	रितु कुमारी	कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय बलियापुर	सरकारी	92.20
2.	रानी प्रमाणिक	एसएसएनएमएस हाई स्कूल आजाद सिजुआ	स्थापना अनुमति	91.20
3.	राखी कुमारी	डीएवी हाई स्कूल कतरासगढ़	सरकारी	90.00
4.	सत्यम डे	डीएवी हाई स्कूल टासरा	सरकारी	89.40

सारणी-4: धनबाद जिला के वर्ष 2017 के टॉप-5 स्कूलों का परिणाम

क्रम सं०	विद्यार्थी का नाम	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	प्राप्तांक
1.	सोनू कुमार साव	राय एकेडमी गोविन्दपुर	स्थापना अनुमति	91.80
2.	नंदिनी झा	कारीटाँड हाई स्कूल मंझलाडीह	स्थापना अनुमति	91.60
3.	चांदनी कुमारी	प्रस्तावित आरएमएस हाई स्कूल, महुदा	स्थापना अनुमति	91.60
4.	सूरज कुमार	संस्कृति विद्या मंदिर हाई स्कूल डिगवाडीह	स्थापना अनुमति	91.40
5.	उत्तम कुमार महतो	प्रस्तावित हाई स्कूल तिलैया, राँगाटाँड	स्थापना अनुमति	91.00

सारणी-5: धनबाद जिला के वर्ष 2018 के टॉप-5 स्कूलों का परिणाम

क्रम सं०	विद्यार्थी का नाम	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	प्राप्तांक
1.	खुशनूमा तहसीन	मिल्लत हाई स्कूल, पाण्डरपाला, वासेपुर	अल्प-संख्यक	93.40
2.	संध्या कुमारी	डीपीएलएमए नावागढ़ कतरास	सरकारी	93.20
3.	गणेश कुमार	जीएनएम प्लस टू हाई स्कूल महुदा	सरकारी	92.80
4.	दीपा कुमारी	प्रस्तावित आरएमएस हाई स्कूल, महुदा	स्थापना अनुमति	92.40
5.	एकता रानी	हाई स्कूल कुमारधुबी	सरकारी	91.80

सारणी-6: धनबाद जिला के वर्ष 2019 के टॉप-5 स्कूलों का परिणाम

क्रम सं०	विद्यार्थी का नाम	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	प्राप्तांक
1.	सचिन कुमार यादव	हाई स्कूल मुगमा	सरकारी	95.80
2.	आयशा कुमारी	रॉयल हाई स्कूल जोड़ापोखर	स्थापना अनुमति	95.40
3.	शोभा कुमारी साव	प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल गोविन्दपुर	सरकारी	95.20
4.	स्वेता कुमारी	हाई स्कूल प्रधानखंता	सरकारी	95.00
5.	राजेश कुमार महतो	हाई स्कूल प्रधानखंता	सरकारी	94.40

5.	सुमन बाउरी	रॉयल हाई स्कूल जोड़ापोखर	स्थापना अनुमति	94.40
----	------------	--------------------------	-------------------	-------

ऑकड़ों का विश्लेषण:-

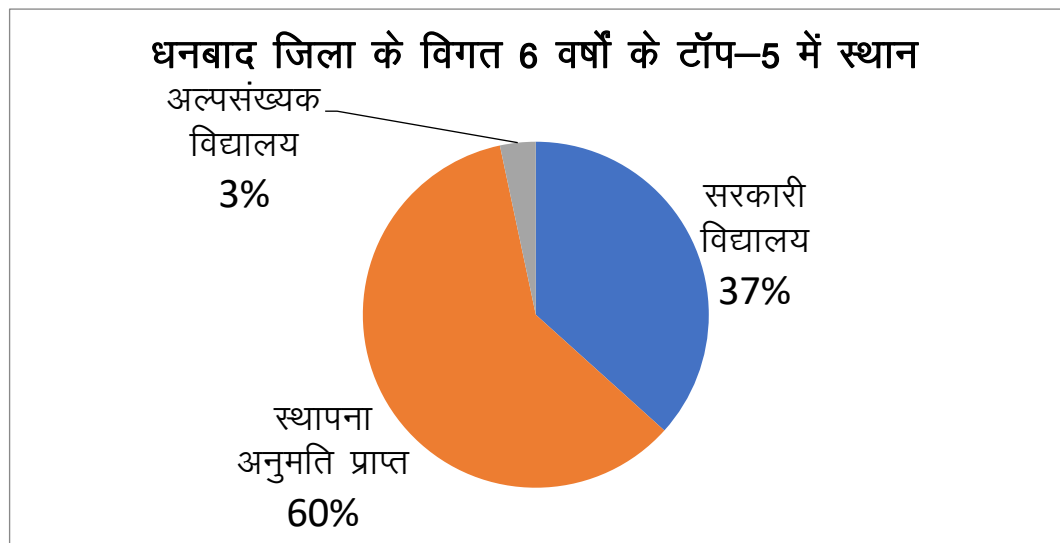
उपरोक्त ऑकड़ों के विश्लेषण करने पर निम्नांकित परिणाम निकलता है-

वर्ष	विद्यालय के प्रकार के अनुसार प्रथम पाँच स्थानों पर आये विद्यार्थियों की संख्या		
	सरकारी विद्यालय	स्थापना अनुमति प्राप्त	अल्प-संख्यक विद्यालय
2019	4	2	0
2018	3	1	1
2017	0	5	0
2016	3	1	0
2015	0	5	0
2014	1	4	0
कुल	11	18	1

सारणी-7: धनबाद जिला के वर्ष 2014 से 2019 तक के टॉप-5 स्कूलों का परिणाम

उपरोक्त पाँच वर्षों के परिणाम में सबसे खास बात देखने को मिली वो ये कि वे सभी विद्यालय जहाँ के विद्यार्थी टॉप-5 में स्थान बनाये हैं, वे सभी ग्रामीण क्षेत्रों से ताल्लूक रखते हैं और इनमें से अधिकांश निजी विद्यालय है। सारणी संख्या-7 से स्पष्ट है कि पिछले छह वर्षों में परीक्षा परिणाम में कुल 30 विद्यार्थियों में 11 विद्यार्थी सरकारी विद्यालयों में पढ़कर जिला के टॉप-5 विद्यार्थियों में स्थान बनाये हैं, जबकि गैर-सरकारी शिक्षण स्थानों में पढ़ने वाले बाकि के 19 स्थानों में कब्जा जमाये जिसमें 18 विद्यार्थी स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालय से हैं और केवल एक विद्यार्थी ने अल्प-संख्यक विद्यालय में पढ़ाई की।

प्रतिशत ऑकड़ों में विश्लेषण करने पर परिणाम इस प्रकार है। 6 वर्षों वार्षिक माध्यमिक परीक्षा जो झारखण्ड एकाडमिक काँसिल, राँची के द्वारा निर्गत किया गया उसमें धनबाद जिला के प्रथम पाँच स्थानों की स्थिति का अध्ययन करने में पाया गया कि कुल 60 प्रतिशत विद्यार्थी स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालयों से ताल्लूक रखते हैं जबकि 37 प्रतिशत विद्यार्थी सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत थे। ऑकड़ों को पाई चार्ट में प्रतिशत में विश्लेषण कर चित्र संख्या-1 में दर्शाया गया है।



पाई चित्र सं0-1: मैट्रिक परीक्षा में धनबाद जिला के विगत छह वर्षों के प्रथम पाँच स्थानों के विद्यार्थियों का प्रतिशत गणना

निष्कर्ष:-

उपरोक्त स्थित पाई चित्र संख्या-1 के नतीजे के अनुसार धनबाद जिला का मैट्रिक की परीक्षा में टॉप-5 स्थानों में विद्यार्थियों के परीक्षाफल से निम्नांकित परिणाम निकलते हैं—

- जिले के प्रथम-5 स्थानों में आने वाले विद्यार्थियों में 60 प्रतिशत विद्यार्थी स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत थे।
- 37 प्रतिशत विद्यार्थी सरकारी विद्यालयों में पढ़कर प्रथम पाँच स्थान में काबिज होने में सफल रहे।
- मात्र तीन प्रतिशत विद्यार्थी प्रथम पाँच स्थानों में अल्पसंख्यक विद्यालय के बच्चे आये।
- प्रत्येक साल के आँकड़ों को देखने पर गैर-सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का परीक्षाफल सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों के अपेक्षा बेहतर रहा है।
- वर्ष 2015 और 2017 में सरकारी विद्यालय के एक भी विद्यार्थी प्रथम-5 स्थान में नहीं आये। शहरों में अवस्थित सरकारी स्कूलों का परीक्षा परिणाम भी बेहतर नहीं हुआ जबकि यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के अपेक्षा सुविधायें अधिक हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालय सभी टॉप-5 स्थानों में काबिज हो गये।
- 2019 में सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए प्रथम-5 में चार स्थान प्राप्त किये, जबकि दो स्थानों में स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालय के विद्यार्थी थे।
- वर्ष 2018 में अल्पसंख्यक स्कूल की एक छात्रा ने जिला में प्रथम स्थान प्राप्त करने में सफलता पायी।

संदर्भ-सूची:

1. पाठक, पी.डी. एवं गुरुशरण दास त्यागी (2017): 'भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं विकास', श्री विनोद पुस्तक भण्डार, आगरा।
2. भटनागर, सुरेश (2011): 'आधुनिक भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ', आर0 लाल बुक डिपो, मेरठ।

3. शर्मा, आर0 ए0 (2014): 'भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास', आर0 लाल बुक डिपो, मेरठ।
4. दैनिक जागरण समाचार पत्र, 13 जून 2018, पृष्ठ संख्या—8
5. दैनिक जागरण समाचार पत्र, 17 मई 2018, पृष्ठ संख्या—10
6. कार्यालय रिपोर्ट, जिला शिक्षा पदाधिकारी, धनबाद